(ii) Review by Government on the working of the Corporation.

[Placed in Library. *See* No. LT—1750/72 for **(i)** and (ii).]

MOTION *RE* FOURTH PLAN MID-TERM APPRAISAL- contd.

श्री एन० एच० कुम्भारे (महाराष्ट्र) : माननीय उपसभापति महोदय, चतुर्थ योजना के मूल्यांकन में जहां तक मजदूरों का सवाल है, मुझे उनके लिए कोई निर्देश नजर नहीं आता हैं । जहां तक मजदूरों की परिस्थिति का सवाल है, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज देश में ऐसे लाखों मजदूर हैं, जिन्हें आज भी न्यूनतम वेतन प्राप्त नहीं होता है । उन मजदूरों को आप छोड़ दीजिए जिनके अपने संगठन हैं, जहां वे संगठित उद्योग में काम करते हैं, जहां मजदूरों को अच्छा वेतन भी मिलता है और बोनस आदि भी मिलता है और ऐसे मजदूरों को मजदूर विषयक कानूनों के सारे फायदे उपलब्ध हैं, किन्तु हमें उन मजदूरों को नहीं भूलना चाहिए, जिनकी संख्या लाखों में है तथा उनको आज भी किसान वेतन भी नहीं मिल पाता है । मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि बीड़ी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की यही स्थिति है । महाराष्ट्र में वहां करीब 2 लाख मजदूर इस उद्योग में काम करते हैं मेरी जानकारी के मुताबिक सारे भारत में करीब-करीब 20 लाख मजदूर बीड़ी उद्योग में काम करते है । उन्हें क्या वेतन मिलता है ? उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस की जानकारी ली जाय तो एक बीड़ी बनाने वाले मजदूर को जो दस घण्टे, बारह घण्टे काम करता है, की मजदूरी सिर्फ दो या ढाई रुपया मजदूरी मिलती है । आज इस मंहगाई के जमाने में दो, ढाई रुपया जिसको मजदूरी मिलती है, वह कैसे जी सकता है, इस को आप सोचें । इसका अंदाजा उपाध्यक्ष महोदय, आप ही लगा सकते हैं । मैं आगे जा कर कहना चाहूंगा कि मैंने सिर्फ 20 लाख मजदूरों की बात कही है, मगर उनके आश्रित का भी विचार किया जाय तो यह समस्या 25, 50 लाख लोगों की है । अगर यह 50 लाख लोगों को एक फेयर डील मिलता है, उन लोगों के साथ जिसको सामाजिक न्याय किया जाता है, तो मेरे खयाल से जो गरीबी हटाओ का स्लोगन है वह सफल हो सकता है, इससे उन्हें कुछ राहत मिल सकती है, उनकी परिस्थिति में कुछ सुधार हो सकता है । मैं यह कहने जा रहा हूं कि इस देश में लाखों मजदूर हैं जो संगठित न होने के कारण बहुत कम वेतन पाते हैं और उनको बहुत कम वेतन पर काम करना पड़ता है । इसका हल क्या है ? मेरे खयाल से इसका एक ही हल 'मिनिमम वेतन' है विभिन्न प्रांतों में वेतन कमेटियां बैठती हैं, वह विभिन्न उद्योगों में वेतन निर्धारित करती हैं, लेकिन बहुत बार वह वेतन भी किसान वेतन के अनुसार नहीं होता । मेरा अनुभव है कि किसान वेतन कमेटियों में जो कारखानेदारों के नुमाइन्दे होते हैं, वह वजन डाल कर और मजदूरों के नुमाइन्दों को मजबूर करके जो न्यायपूर्ण वेतन निर्धारित होना चाहिए वह नहीं होने देते हैं और इस प्रकार न्यायपूर्ण वेतन भी निर्धारित नहीं किया जाता है ।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि जहां तक खेती में काम करने वाले मजदूरों की हालत का सवाल है, उन बेचारों को साल में दो चार महीने ही काम मिलता है । उस खेत का मालिक अगर कहेगा कि दो रुपये में काम करो तो दो रुपये में ही उसको काम करना पड़ेगा । क्या हमने उन लाखों मजदूरों के विषय में विचार किया है । विचार अभी तक नहीं हुआ है । इसका हल क्या है ? मेरे दृष्टिकोण से इसका एक ही हल है राष्ट्रीय मिनिमम वेतन निर्धारित किया जाय, ऐसा वेतन निर्धारित किया जाय कि मजदूर कहीं भी काम करे, चाहे कारखाने में काम करे, चाहे खेती में काम करे, छोटे कारखाने में काम करे या बड़े कारखाने में काम करे, कोई भी उद्योग में काम करे, न्यूनतम वेतन मिले । न्यूनतम वेतन कार्यान्वित किया जाये । मजदूर को उसकी मेहनत का पूरा-पूरा वेतन मिलना चाहिये । हमारी योजना जहां तक मजदूरों का सवाल है इसके बारे में कोई निर्देश नहीं है । जहां हम योजना की बात

[श्री एन० एच० कुम्भारे]

कहते हैं वहां उसमें कई और बातें आ जाती हैं जैसे कि कैपिटल फार्मेशन, सेविंग, मोबिलाइजेशन आफ रिसोर्सेज कई बातें आती हैं, लेकिन जहां तक मजदूरों को न्यायपूर्ण वेतन देने का सवाल है, उसमें कोई विशेष कदम उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कानून बनाने को तथा एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यवाही की आवश्यकता है। एक कानून बनाया जाय और उस कानून का अमल होने से मजदूरों को न्यायपूर्ण वेतन मिलेगा। जो शोषित तथा पीड़ित हैं, मेहनत करने के बाद भी जिनको कुछ नहीं मिलता। इन सारे मजदूरों को राहत मिलेगी। इसलिए नेशनल मिनिमम वेजेज लागू किया जाय इस विषय में अनेक संगठनों ने आवाज उठाई है, लेकिन यह कहा जाता है कि हमारा देश धनी नहीं है कि हम राष्ट्रीय मिनिमम वेज दे सकें। यदि मजदूर को उसका न्यायपूर्ण वेतन नहीं दिया जाय तो गरीबी कैसे दूर होगी। इसलिए हमारा सुझाव है कि राष्ट्रीय मिनिमम वेतन के लागू करने के लिए योजना आयोग को कदम उठाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां गरीबी हटाओ की बात कही जाती है। उस संदर्भ में हमें देखना चाहिये कि कौन देश में गरीब है, किस की गरीबी हटानी चाहिये। तो मैं कहना चाहता हूं कि वह मजदूर है जिसको मेहनत करने के बाद भी न्यायपूर्ण वेतन नहीं मिलता और वह मजदूर है जो कि खेतों में काम करता है और जिसको कि डेढ़ रुपये से लेकर दो रुपये रोजी मिलती है और एक है छोटे काश्तकार का, वह काश्तकार जिसके पास अलाभकर जोत है। मैं एक गांव में गया और एक काश्तकार से पूछा कि देश में तो इतनी बड़ी योजनायें चल रही हैं, आप योजनाओं का फायदा क्यों नहीं उठाते। तेरे पास दो एकड़ जमीन है लेकिन मैं देख रहा हूं कि तेरी आज भी वही हालत बनी है, सारी योजनायें चल रही हैं, तू इनका फायदा क्यों नहीं उठाता, क्यों नहीं एक कुवां खोद लेता, जिससे कि ज्यादा उत्पादन होगा तो उसने कहा कि अगर मैं कुवां खोदने की बात करता हूं तो मुझे कम से कम पांच हजार रुपया चाहिये और अगर मैं पांच हजार रुपया लेने के लिये बैंक में जाऊं तो उस का मिलना असम्भव है और अगर पांच हजार रुपया मिल भी गया और कुवां मैंने खोद भी दिया लेकिन अगर कुंए में पानी नहीं मिला तो मेरा पांच हजार रुपया निकल जायगा और फिर मेरी यह जमीन भी हाथ से चली जायगी। हम खेती सुधारने की बात करते हैं और सीलिंग की बात करते हैं तो मेरे खयाल से यह आपका अधूरा कदम है। सीलिंग से खेती सुधार के कार्य में पूरी सफलता नहीं मिलेगी। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि जब तक देश के अन्दर जमीन का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायगा, तब तक कोई भी खेती की सुधार की योजनाएं पूरी तरह से अमल में नहीं आयेंगी। जो छोटा काश्तकार होता है जिसके पास थोड़ी जमीन है उसके पास उस जमीन का पूरा उपयोग (फुल युटिलाइजेशन) करने की पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, शिक्षा नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिये अगर आप चाहते हो कि जितनी भी देश के अन्दर जमीन है उसका फुल युटिलाइजेशन किया जाय। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि जमीन का राष्ट्रीयकरण किया जाय। मैं वह अपनी तरफ से कोई नई बात नहीं कहता हूं, इसके बारे में अपने देश में भी काफी विचार हुआ है। मेरे खयाल से दस साल के पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब नागपुर में अधिवेशन हुआ था, तो उसमें जमीन के राष्ट्रीयकरण करने की बात भी कही गई थी और उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अब लोगों को छोटी-छोटी जमीन रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर देश में जमीन का फुल युटिलाइजेशन करना है, देश का उत्पादन बढ़ाना है तो एक ही रास्ता है कि जमीन का राष्ट्रीयकरण किया जाय। यदि साहस के साथ कदम नहीं उठाया गया तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की सफलता नहीं होगी और मैं उम्मीद करता हूं, मेरे सुझाव पर भी योजना कमिशन विचार करेगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2 P. M.

The House then adjourned for lunch at fifty-six minutes past twelve of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock, MR. DEPUTV CHAIRMAN in the Chair.

MOTION *RE* FOURTH PLAN MID-TERM *APPRAISAL—Continued*

SHRI BIPINPAL DAS (Assam) : Mr. Deputy Chairman, Sir, I take this opportunity to congratulate you personally on your election to this high office. I recollect today long association with you for long years, and the day in 1950 went I met you first in Madras when I went to attend the Socialist Party Conference. For all these years, I have known you and I have admired your qualities of head and heart. Please accept my congratulations on this occasion today.

Sir, we must also thank the Minister for Planning for giving us the opportunity, today, or these days, to make a mid-trem appraisal of the Fourth Plan in order to examine where we have failed and, if possible, to sugggest corrective measures. It is good that he has done it at the beginning of the year so that we can go ahead with a little more clearer thinking. But, Sir, this Mid-term Appraisal document has shown that we have failed to achieve the targets or make adequate and satisfactory progress on a number of items in a number of sectors, and they have also indicated in this document that by the time the Fourth Plan will come to an end it would not be possible to achieve the targets on a number of items. I naturally expected that the Planning Commission and the Planning Ministry would also clearly analyse the causes of our failure and suggested the corrective measures. They have suggested some but for myself I must say I am not satisfied with whatever corrective measures they have suggested. As a matter of fact, the basic causes have not been analysed at all. Anyway, I would leave it at that.

Sir, some programmes have been suggested for welfare measures like drinking water supply, rural housing, rural electricity, elementary education, health, sanitation, and all that. There is no doubt that all these programmes are very good and they been long overdue. It is time that we undertake a massive programme of social welfare measures in order to do good to the people of the rural areas, to the poorer sections and backward classes all that, and therefore I welcome these measures. But then these welfare measures ultimately do not solve our problem. We have raised the slogan of *garibi hatao.* We want to banish poverty. We want to achieve self-reliance. We want to banish proverty from this land, to help the last men in the society to raise his standard of living, at least to make a giving. But I do not think all these social welfare programmes constitute an assault on poverty in this country. There may be supplementary programmes. They are quite good. I welome them, but they do not constitute, as I said assault on poverty.

In this country our objective is "Garibi Hatao" banishing poverty. Therefore, the emphasis hence forward must be on production of goods of mass consumption, so that the poor, the backward classes, the neglected man and the last man in the society may be able to satisfy his or their daily needs. We have to provide him with two wholesome meals a day, a house to live in, some arrangements for health and hygiene and clothes to wear and all that. But production alone is not enough. Even we produce these things, even if we adopt a mass programme for production of such essential goods which are necessary for the masses, even if we succeed in doing that, the problem is not solved. We must side by side, simultaneously be able to provide purchasing power to the common man. Therefore, ultimately the question comes to one of solving the problem of unemployment and under-employment. That it becomes the basic question. In the ultimate analysis if we want to launch an assault on poverty the poorest man must be given the wherewithal by which he can earn a decent living, at least a minimum standard of living. Only then the whole programme will be meaningful and it will acquire some substance

Some people believe and even the earlier Planning Commissions used to believe that economic growth alone would eliminate poverty and provide social justice. Experience has shown that it was an entirely wrong conception. During the last twenty years of planning we have certainly made some progress. In the matter of economic development some growth is there. There is no doubt about it. But the fruits of our economic deve-